



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1941 (श0)

(सं0 पटना 559) पटना, वृहस्पतिवार, 25 अप्रील 2019

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी 2019

सं0 से0प्र0उप0-26/विविध-07-02/2018-1725(S)—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 159 क के उप नियम (iii) को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं:-

“(iii) (क) अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार की योजनाओं के विभागीय कार्य हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता सम्यक् विचारोपरान्त आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार के आदेश हेतु समर्पित करेंगे।

अनुमोदन देने हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होंगे :-

क्रमांक	कार्य की राशि	आदेश हेतु सक्षम प्राधिकार
1	₹3.5 करोड़ तक के कार्य।	मुख्य अभियंता
2	₹3.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के कार्य।	प्रधान सचिव/सचिव
3	₹5 करोड़ से ₹15 करोड़ तक के कार्य।	विभागीय मंत्री

(ख) विभागीय कार्यों हेतु सामग्रियों की आपूर्ति Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन प्राप्त कर किया जायेगा। निर्माता सरकारी प्रतिष्ठानों से सामग्री सीधे क्रय की जा सकेगी। श्रमिकों का भुगतान Labour Contract के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) यथा संभव विभागीय Tools & Plants का प्रयोग कर विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराए जाएँगे। विभागीय रूप से Tools & Plants की अनुपलब्धता की स्थिति में Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से Tools & Plants Hire कर कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य को Piece Rate Basis पर Bihar Financial Rules के अनुसार निविदा/कोटेशन आमंत्रित कर कराया जा सकेगा।

(ङ) सामग्रियों/सेवाओं/Tool & Plants आदि के लिये आपूर्तिकर्ता/प्रदाताओं का Panel वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बना लिया जायेगा। इस हेतु तकनीकी योग्यता संबंधी प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। तकनीकी रूप से योग्य आपूर्तिकर्ता/प्रदाताओं से वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर कार्यवार वित्तीय निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर आपूर्ति ली जायेगी।

(च) विभागीय कार्यों के स्वीकृति के पूर्व डिजाईन/प्राक्कलन तैयार किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी कार्य प्राक्कलन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यान्वित किया जायेगा। साथ ही बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) विभागीय कार्यों में अस्थायी अग्रिम की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी बल्कि आपूर्तिकर्ता को सीधे चेक/ऑन-लाईन माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान किया जायेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 18th February 2019

No. से0प्र0उप0-26/विविध-07-02/2018-1725(S)--In exercise of the powers conferred under Article 166(3) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to substitute the sub rule (iii) of 159 A of the Bihar Public Works Department Code, Volume-1(1958) (as amended from time to time) by the following with immediate effect :-

"(iii) (a) For very urgent/emergent nature projects, the proposal for Departmental work approval shall be submitted to competent authority by the Executive Engineer after necessary consideration.

The competent Authority for according approval shall be as follows :

S. No	Amount of Work	Competent Authority for according approval
1.	Work up to ₹3.5 Crores.	Chief Engineer
2.	Work more than ₹3.5 to 5 Crores	Principal Secretary/Secretary
3.	Work more than ₹5.00 Crores to ₹15 Crore.	Departmental Minister

- (b) The materials for Departmental work shall be procured as per Bihar Financial Rules by way of tender/quotations. The material shall be purchased directly from manufacturing Government Enterprises.
- (c) As far as possible, the departmental work shall be executed using departmental tools and plants. In case of non-availability of departmental tools & plants, the works will be executed by hiring through tender/quotations.
- (d) The works of special technical nature shall be executed on Piece Rate Basis as per Bihar Financial Rules.
- (e) A panel of Suppliers/ Providers shall be made in the beginning of the financial years. For this purpose, the provision relating to technical eligibility criterion shall be framed by the Administrative Department. The materials shall be purchased, from time to time, from the technically qualified suppliers/ providers during the financial year through work wise invitation of financial tender/quotations.
- (f) The design/ Estimate shall be prepared before approval of the departmental work. The work based on estimate shall be executed only after the approval of the competent authority. Also the other conditions of the Bihar Public Works Department Code shall be ensured to be followed.
- (g) There shall be no provision for temporary advance rather the payment shall be made by cheque/ online directly to supplier by the Executive Engineer."

By order of the Governor of Bihar,
Ratnesh Kumar,
Joint Secretary of the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 559-571+1000 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>